आरजीपीवी की विद्यार्थियों-कर्मचारियों से भरी बस खंभे से टकराई

सुबह के समय वीआइपी रोड पर हुआ हादसा, स्टाफ-छात्रों सहित १० घायल, बस चालक की लापरवाही से हुआ हादसा

भोपाल, (एजेंसी)। राजधानी के कोहेफिजा थाना इलाके में वीआईपी रोड पर मंगलवार सुबह करीब १० बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई जब राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) की विद्यार्थियों और कर्मचारियों से भरी बस बिजली के खंभे से टकरा गई। बताया गया है की बेकाबू बस राजा भोज प्रतिमा और करबला के बीच मोड़ पर अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर एक खंभे से भिड़ गई। मौके पर मौजूद लोगो का कहना है की खंभे का सहारा मिलने से बस पलटने से बच गई। एक्सीडेंट में जहॉ बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई वहीं करीब १५ लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। इनमें दो विद्यार्थी और एक कर्मचारी को गंभीर चोटें आाई है। बस में सवार घायल छात्र सुमित पवार आरजीपीवी में सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा सेकेंड ईयर के छात्र है। वे माता मंदिर से बस में सवार हुआ था। उनका कहना है की वे लोग करीब आधे घंटे लेट हो गए थे। इसके बाद बस चालक ने तेज रफ्तार में बस चलाई। वीआईपी रोड पर बस का अगला टायर डिवाइडर पर चढ़ गया, जिसके बाद बस पलट गई। एक्सीडेंट में बसंत नाम के छात्र के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि खुशी नाम की छात्रा की आंख के ऊपर चोट आई है। एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। अन्य घायलों को मामूली चोटें आई हैं। घटना को आरजीपीवी प्रबंधन ने दुखद बताते हुए कहा कि आधा दर्जन से अधिक छात्र घायल हुए थे, जिनमें से ४-५ को छुट्टी मिल चुकी है। एक-दो को जल्द छुट्टी दी जाएगी, जबकि एक छात्र को सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। हादसे में घायल विद्यार्थियों के साथ बस में डयूटी पर तैनात तीन स्टाफ सदस्य भी शामिल हैं। वहीं कोहेफिजा पुलिस ने बताया कि बस सुबह १२ नंबर क्षेत्र से आरजेपीवी के विद्यार्थियों को लेकर जा रही थी। दुर्घटना के समय बस में करीब ५० विद्यार्थी और कर्मचारी सवार थे। वीआईपी रोड पर मोड़ के दौरान बस की रफ्तार अधिक थी। चालक बस को नियंत्रित नहीं कर पाया और बस डिवाइडर से टकराने के बाद खंभे से जा लगी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुचीं और बस को सीधा कर उसमें सवार लोगों को बाहर निकालकर घायलो को उपचार के लिये हमीदिया अस्पताल पहुचांया गया। हादसे में घायल विद्यार्थियों के साथ बस में डयूटी पर तैनात तीन स्टाफ सदस्य भी शामिल हैं। पुलिस हादसे के कारणों की जॉच कर रही है, इसमें बस चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के बिंदु की भी जांच की जा रही है।

- ड्राइवर ने बताई बस के सामने अचानक व्यक्ति के आने की बात

पहुंची की शुरुआती पूछताछ में बस ड्राइवर ने बताया कि बस के सामने अचानक एक व्यक्ति आ गया था। उसे बचाने के प्रयास में वह बस पर से नियंत्रण खो बैठा और बस बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकरा गई।

मध्यप्रदेश हाईकोर्टमें सात नए जजों की नियुक्तिको कालेजियमकी मंजूरी

जबलपुर, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात अधिवक्ताओं को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें जबलपुर के तीन अधिवक्ता भी शामिल हैं सोमवार को हुई कॉलेजियम की बैठक में डॉ. विवेक शरण (इंदौर), राजेश कुमार शुक्ला (ग्वालियर), कनक गहरवार उर्फ कनक लता सिंह (जबलपुर), भक्ति व्यास (इंदौर), श्रेयस पंडित (जबलपुर), मृणाल एलकर उर्फ मृणाल मजुमदार (नई दिल्ली) और अविनाश जरगर (जबलपुर) के नामों पर सहमति बनी। वर्तमान में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ३८ न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या ५३ है। सातों अधिवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर ४५ हो जाएगी। इसके बावजूद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के आठ पद रिक्त रहेंगे। कॉलेजियम की मंजूरी के बाद अब नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। सात नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से हाईकोर्ट में न्यायिक कार्यों के संचालन को गति मिलने और लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद है।

६ माह में निकायों में रिश्वत लेते ५ कर्मचारी गिरफ्तार

२०१३ से अब तक ५९ अधिकारी-कर्मचारी लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की जांच के दायरे में.महंगी खरीदी के मामले में लोकायुक्त ने भी शुरू की जांच, मंत्री की चुप्पी पर उठ रहे सवाल

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में खरीदी की कथित गड़बड़ियों के बीच रिश्वतखोरी के मामले भी सामने आ रहे हैं। एक ओर ई-नगर पालिका और जेम पोर्टल के आंकड़ों के विश्लेषण में करीब २५० करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं के संकेत मिलने की बात कही जा रही है, तो दूसरी ओर लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई में अप्रैल से सितंबर २०२६ के बीच चार मामलों में पांच अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े गए। वर्ष २०१३ से अब तक निकायों के ५९ अधिकारी-कर्मचारी लोकायुक्त और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की जांच के दायरे में आ चुके हैं। खरीदी में कथित गड़बड़ी के मामले में लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई) ने स्वत: संज्ञान लेकर जांच शुरू की है। इस बीच नगरीय विकास एवं आवास विभाग की निगरानी व्यवस्था, खरीदी प्रक्रिया की पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन करीब २५० करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं के मामले में विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की सार्वजनिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

लोकायुक्त पुलिस की अप्रैल से सितंबर २०२६ के बीच की कार्रवाई में नगरीय निकायों के पांच अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े गए। इनमें रायसेन जिले की नगर परिषद उदयपुरा के उपयंत्री और नगर पालिका मंडला के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) शामिल हैं। दोनों पर दो-दो लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में कार्रवाई हुई। इसके अलावा नगर पालिका नरसिंहपुर के एक लिपिक को २५ हजार रुपये और जबलपुर जिले की पनागर नगर परिषद के उपयंत्री व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को ४० हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। इन मामलों में निर्माण कार्य की सुरक्षा निधि, अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने, ठेकेदार के भुगतान के बाद एफडीआर और बैंक गारंटी लौटाने तथा नल-जल योजना के काम से जुड़े मामलों में रिश्वत मांगने के आरोप हैं।

१३ साल में ५९ अधिकारी-कर्मचारी जांच के घेरे में

नगरीय निकायों में भ्रष्टाचार की शिकायतें केवल हाल के महीनों तक सीमित नहीं हैं। वर्ष २०१३ से अब तक नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों के ५९ अधिकारी-कर्मचारी लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की जांच के दायरे में आए हैं। इनमें अधिकांश मामले कथित तौर पर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने से जुड़े हैं, जबकि कुछ मामलों में आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं। इन प्रकरणों में विभागीय अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद अदालत में चालान पेश किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह स्थिति बताती है कि निकायों में भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के साथ अभियोजन की प्रक्रिया भी अहम है। हालांकि, जांच के दायरे में आने या गिरफ्तार होने का अर्थ दोष सिद्ध होना नहीं है। संबंधित मामलों का अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया से तय होगा।

२५० करोड़ की खरीदी में गड़बड़ी के संकेत, लोकायुक्त ने मांगे दस्तावेज

निकायों में सामग्री खरीदी का मामला अब जांच के दायरे में है। विभागीय स्तर पर ई-नगर पालिका पोर्टल और जेम पोर्टल के आंकड़ों का एआई की मदद से विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, खरीदी के रिकॉर्ड में अंतर सामने आने के बाद करीब २५० करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठा। इसके बाद ३९२ अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है। विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त ने स्वत: संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू की है। एसपीई के महानिदेशक योगेश देशमुख के मुताबिक, नगरीय विकास एवं आवास विभाग से संबंधित जानकारी मांगी जा रही है। दस्तावेजों के परीक्षण के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा है कि लोकायुक्त संगठन द्वारा मांगी जाने वाली जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि रिकॉर्ड में मिले अंतर की प्रकृति क्या है, किन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है और सरकारी खजाने को वास्तविक नुकसान हुआ है या नहीं।

तीन साल की खरीदी पर उठे निगरानी के सवाल

करीब तीन साल की अवधि में हुई खरीदी के रिकॉर्ड में कथित अनियमितताओं के संकेत मिलने से निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। यदि पोर्टल के आंकड़ों के विश्लेषण से बड़े अंतर सामने आए, तो यह भी जांच का विषय होगा कि खरीद के समय उनका पता क्यों नहीं चला और सत्यापन की मौजूदा व्यवस्था कितनी प्रभावी थी। अप्रैल में भोपाल में नगरीय निकायों के अधिकारियों की कार्यशाला के दौरान अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने इस मामले को सामने रखा था। इसके बाद विभागीय कार्रवाई का मुद्दा चर्चा में आया। अब लोकायुक्त जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि कथित गड़बड़ियां किन प्रक्रियाओं में हुईं और जिम्मेदारी किस स्तर पर तय होती है। मामले में विभागीय अधिकारी कार्रवाई और जांच से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उनसे फोन और वाट्सएप संदेश के जरिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन जवाब नहीं मिला। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच कराने की बात कही है।

पति- पत्नी ने एक साथ फांसी लगाकर की आत्महत्या

दूसरे कमरे में सो रहे थे बच्चे, कारण अज्ञात

भोपाल, (एजेंसी)। राजधानी भोपाल के देहात क्षेत्र के ईंटखेड़ी इलाके में रायपुर गांव में रहने वाले पति-पत्नी द्वारा एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या किय जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। दंपती के १५ और १३ साल के दो बच्चे हैं, जो घटना के समय घर के दूसरे कमरे में सो रहे थे। सुबह पति-पत्नी के शव मिलने से आसपास सनसनी फैल गई। थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक सुरेंद्र सिलावट और उनकी पत्नी मोना मेंहनत-मजदूरी का काम करते थे। घटना २५ अक्टूबर की रात की बताई जा रही है। पुलिस का कहना है की पति-पत्नी घर के एक कमरे में थे, जबकि दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में सुलाया गया था। कमरे का दरवाजा बंद था। सुबह पड़ोसी को सुरेंद्र के घर का गेट खुला दिखाई दिया और अंदर पति-पत्नी के शव फंदे पर लटके नजर आने पर इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। दोनों के शव घर के एक कमरे में पंखे के कुंदे से लटके मिले। मौके पर पहुचीं पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन के बाद मर्ग कायम कर शवो को पीएम के लिये भेजते हुए आगे की कार्यवाही शुरु कर दी है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल खुदकुशी का सही कारण साफ नहीं हो सका है, शुरुआती जॉच में जहॉ पिछले चार-पांच दिनों से पति-पत्नी के बीच विवाद होने की जानकारी सामने आई है। वहीं यह भी पता चला है कि चार दिन पहले मृतक दंपत्ति का पड़ोसी से विवाद हुआ था। पुलिस आत्महत्या से जुड़े सभी बिंदुओ पर जांच कर रही है। छानबीन पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के सही कारणो का पता चल सकेगा, जिसके आधार परआगे की कार्यवाही तय की जायेगी।

कांग्रेस सरकार गिरने पर कांग्रेस में घमासान

दिग्विजय पर सज्जन का पलटवार, बोले- कमलनाथ जितने जिम्मेदार, उतने ही दिग्विजय भी

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के पतन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सरकार गिरने के लिए कमलनाथ को जिम्मेदार ठहराने संबंधी बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार गिरने के लिए जितने दोषी कमलनाथ हैं, उतने ही दिग्विजय सिंह भी हैं। ऐसे में एक-दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय पार्टी को अपनी एकजुटता और मौजूदा राजनीतिक लड़ाई पर ध्यान देना चाहिए। सज्जन वर्मा ने दिग्विजय सिंह के बयान को अनुचित समय पर दिया गया बयान बताया। उनका कहना है कि जब कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी सहित दूसरे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति के तहत काम कर रही है, तब पुराने मामलों को लेकर पार्टी के भीतर आरोप-प्रत्यारोप से संगठन को नुकसान हो सकता है।

सरकार के फैसलों में दिग्विजय की भी भूमिका थी

दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए वर्मा ने कहा कि प्रदेश का बच्चा-बच्चा जानता है कि कमलनाथ सरकार के समय दिग्विजय सिंह की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। वह सरकार के फैसलों और निर्णयों में बराबर दखल रखते थे। ऐसे में केवल कमलनाथ को सरकार गिरने के लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। वर्मा ने साफ कहा कि सरकार के पतन की जिम्मेदारी तय करनी है तो उसमें दोनों नेताओं की भूमिका को देखना होगा। उनके मुताबिक, आपसी दोषारोपण से पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला है।

राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ाई पर जोर

सज्जन वर्मा ने कहा कि मौजूदा समय में कांग्रेस को जनहित के मुद्दों और संगठन की मजबूती पर ध्यान देना चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच सार्वजनिक बयानबाजी से राजनीतिक विरोधियों को मुद्दा बनाने का मौका मिलता है। ऐसे समय में पुराने विवादों को फिर से उठाना पार्टी के हित में नहीं है। उन्होंने अपने बयानों को लेकर कहा कि वह बिना वजह या फालतू बातें नहीं करते, बल्कि परिस्थितियों और बयानों के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं।

पुराने विवाद से फिर उभरी गुटबाजी की चर्चा

कमलनाथ सरकार मार्च २०२० में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने और उनके समर्थक विधायकों के इस्तीफों के बाद अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद भाजपा ने सरकार बनाई थी। इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस में समय-समय पर जिम्मेदारी तय करने की बहस सामने आती रही है। दिग्विजय सिंह के ताजा बयान और सज्जन वर्मा के पलटवार ने एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच आपसी समन्वय पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में पार्टी के सामने चुनौती है कि पुराने घटनाक्रम पर जारी बहस को संगठनात्मक एकजुटता और आगामी राजनीतिक संघर्ष पर हावी न होने दिया जाए।

आय से २.७४ करोड़ अधिक खर्च

जीएसटी अधिकारी के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा, जबलपुर, भोपाल और सागर में एक साथ कारर्वाई, पत्नी और माता-पिता के नाम पर जमीन, मकान व वाहन की जानकारी आई सामने

जबलपुर, (एजेंसी)। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार, २७ अक्टूबर की सुबह राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) विभाग के वाणिज्यिक कर अधिकारी मनीष कुमार जैन के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जबलपुर, भोपाल और सागर में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान अधिकारी और उनके परिजनों के नाम पर दर्ज संपत्तियों, वाहनों, बीमा पॉलिसियों और खर्च से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। लोकायुक्त की प्रारंभिक जांच में अधिकारी की ज्ञात आय और व्यय के बीच करीब २ करोड़ ७४ लाख रुपये का अंतर सामने आया है।

लोकायुक्त के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मनीष कुमार जैन की कुल आय १ करोड़ ३ लाख ७३ हजार ३१७ रुपये आंकी गई, जबकि उनका कुल व्यय ३ करोड़ ७८ लाख २५ हजार ७०७ रुपये पाया गया। इस तरह व्यय ज्ञात आय का ३६४.६४ प्रतिशत बताया गया है। आय की तुलना में २ करोड़ ७४ लाख ५२ हजार ३९० रुपये अधिक खर्च किए जाने का आकलन किया गया है। इसी आधार पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच शुरू की गई है।

शिकायत के सत्यापन के बाद दर्ज किया प्रकरण

लोकायुक्त एसपी अंजूलता पटले को वाणिज्यिक कर अधिकारी मनीष कुमार जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी। निरीक्षक बृज मोहन सिंह नरवरिया ने शिकायत का सत्यापन किया। प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाए जाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ की धारा १३(१)(बी) और १३(२) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसके बाद मंगलवार सुबह करीब ६ बजे जबलपुर, भोपाल और सागर में एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया गया।

परिजनों के नाम पर संपत्तियों की जानकारी

लोकायुक्त की प्रारंभिक जांच में मनीष कुमार जैन के अलावा उनकी पत्नी निधि जैन, पिता कोमलचंद जैन और माता शशि जैन के नाम पर भी संपत्तियां होने की जानकारी सामने आई है। इनमें जबलपुर और भोपाल में जमीन, प्लॉट, बंगला और फ्लैट शामिल हैं। इसके अलावा सागर जिले के बंडा में प्लॉट पर बने मकान का भी पता चला है। जांच के दौरान पत्नी के नाम पर मारुति स्विफ्ट कार और सुजुकी एक्सेस स्कूटर खरीदे जाने की जानकारी भी सामने आई है। अधिकारी और उनके परिजनों के नाम पर बीमा पॉलिसियां होने का उल्लेख भी जांच में किया गया है।

दमोह में पदस्थ हैं अधिकारी

मनीष कुमार जैन जबलपुर की रिलाएबल डेवलपर कॉलोनी में रहते हैं और वर्तमान में दमोह में वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। लोकायुक्त की टीमें विभिन्न ठिकानों से मिले दस्तावेजों और संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही हैं। जांच के बाद संपत्तियों के वास्तविक मूल्य, आय के स्रोत और कथित आय से अधिक संपत्ति के संबंध में स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल कार्रवाई प्रारंभिक जांच के आधार पर जारी है।

पारस की मौत से रांझी में आक्रोश, शव रखकर प्रदर्शन

आरोपितों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग

जबलपुर, (एजेंसी)। रांझी के आजाद नगर गंदी बस्ती क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हुई हिंसक वारदात में घायल पारस यादव की उपचार के दौरान मौत के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। मंगलवार को आक्रोशित क्षेत्रीय नागरिकों ने व्हीकल मोड़ पर शव रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते रांझी के मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता दिलाने और मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व पार्षद राजेश यादव और युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव रोहित सैनी ने घटना पर नाराजगी जताते हुए मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने वारदात में शामिल आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने और हमले में घायल अन्य लोगों को भी आर्थिक सहायता देने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि धार्मिक आयोजन के दौरान हुए विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई और कई लोग घायल हुए हैं। ऐसे में पीड़ित परिवारों को राहत देने के साथ आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

भंडारे के दौरान शुरू हुआ था विवाद

रांझी थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि रविवार रात रांझी के आजाद नगर क्षेत्र में नवरात्रि के बाद भंडारे का आयोजन किया जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से बाइक निकालने को लेकर कुछ युवकों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि बाइक सवार युवक वहां से जाने के कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर वापस पहुंचे। इसके बाद विवाद बढ़ गया और लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। बीच-बचाव करने पहुंचे लोगों पर भी हमला किया गया। घटना में कई लोग घायल हुए, जिनमें कुछ को गंभीर चोटें आईं।

वेंटिलेटर पर था पारस, इलाज के दौरान मौत

हमले में सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण ५० वर्षीय पारस यादव को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा था, लेकिन सोमवार रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना में घायल रवि गोटिया, रागिनी गोटिया, पप्पू वर्मा, अनुज कोल, बिट्टू झरिया और मनीष गोटिया सहित अन्य लोगों का उपचार जारी है।

आरोपित गिरफ्तार, प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा

पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी समीर वंशकार सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। पारस की मौत के बाद क्षेत्र में बढ़े आक्रोश को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने और मामले में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रदर्शन के कारण बाधित यातायात और तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मौके पर तैनात रही।

इलाज के दौरान तोड़ा दम, ६ आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामलें में आरोपी समीर वंशकर, रोहित, यश और छोटू सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू और लाठी भी बरामद की है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

मुफ्त लगे स्मार्ट मीटर बने जी का जंजाल

तकनीकी गड़बड़ी से जल रहे टर्मिनल, उपभोक्ताओं की जेब हो रही ढीली

भोपाल (ईएमएस)। प्रदेश में उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर आर्थिक बोझ बनते जा रहे हैं। बिजली कंपनी अनियमित वॉल्टेज या अन्य कारणों से मीटर जलने पर उपभोक्ताओं से ५,५०० रुपये तक का बर्न चार्ज वसूल रही है। इसके अलावा मीटर को दूसरे स्थान पर लगाने के दौरान बाहरी सील टूटने पर उपभोक्ताओं को ४०० रुपये का री-सील शुल्क देना पड़ रहा है। बिजली कंपनी की इस व्यवस्था के कारण उपभोक्ताओं को अचानक ५ हजार से लेकर ६ हजार रुपये तक का शुल्क चुकाना पड़ रहा है।

जिले में अब तक ४ लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। इनमें से ६० हजार उपभोक्ताओं के यहां ये मीटर दो साल पहले लगे थे। ये मीटर बेहद संवेदनशील हैं, जिसके कारण वॉल्टेज में गड़बड़ी या केबल फॉल्ट की वजह से इनके टर्मिनल जल जाते हैं। बाहर से मीटर चालू दिखाई देता है लेकिन घर के भीतर वॉल्टेज की समस्या बन जाती है। शिकायत करने पर कंपनी बर्न चार्ज और रीसिल शुल्क लगाती है। विशेषज्ञ स्मृति आंजना के अनुसार तीन से चार साल बाद जब मीटरों में गड़बड़ी शुरू होगी, तब उपभोक्ताओं पर शुल्क का भार और बढ़ेगा।

टैरिफ के माध्यम से वसूली की कवायद

राजहर्ष कॉलोनी में एक उपभोक्ता के घर में केबल जलने से खराबी आई, जिसके बाद लाइन स्टाफ ने जांच करके ५ हजार रुपये शुल्क बता दिया। केंद्र की आइपीडीएस योजना के तहत बिजली कंपनी ने स्मार्ट मीटर मुफ्त लगाए थे लेकिन अब कंपनी ने इन्हें टैरिफ दर से जोड़ दिया है। कंपनी ने मौजूदा टैरिफ में ही स्मार्ट मीटर के नाम पर १५५ करोड़ रुपये जोड़े हैं। कंपनी अब इसे बिजली आपूर्ति खर्च मानकर टैरिफ के माध्यम से वसूल रही है। बिजली कंपनी इस साल भोपाल के सभी घरों में स्मार्ट मीटर स्थापित कर देगी।

पुलिस चौकी पर पेट्रोल बम फेंकने वाले को ४ साल की कैद

जबलपुर, (एजेंसी)। जबलपुर जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौहान की अदालत ने गोरखपुर थानांतर्गत रामपुर मांडवा पुलिस चौकी पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में आरोपित जबलपुर निवासी परवेज अखार उर्फ नावेद अंसारी को दोषी करार देते हुए चार साल के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने प्रकरण में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। मामले में सुनवाई के दौरान अदालत में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक लहर दीक्षित ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार, १८ अप्रैल २०२३ की रात करीब दो बजे आरोपित ने अपने तीन अन्य नाबालिग साथियों के साथ मिलकर मांडवा स्थित पुलिस चौकी पर पेट्रोल बम फेंके थे। इस घटना में पुलिस चौकी को आर्थिक क्षति पहुंची थी। घटना के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चारों आरोपितों को हिरासत में लिया था। इनमें शामिल तीन अपचारी बालकों के विरुद्ध किशोर न्याय बोर्ड में मामला विचाराधीन है। वहीं, वयस्क आरोपित परवेज अखार उर्फ नावेद अंसारी के विरुद्ध अदालत में विचारण पूरा हुआ। सुनवाई के बाद अदालत ने उसे दोषी पाते हुए चार साल के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

मप्र में ८.६६ लाख विद्यार्थियों का नामांकन घटा

स्कूल शिक्षा विभाग ने १२ से अधिक जिलों के अधिकारियों को थमाए नोटिस, भोपाल में २०,३४७ विद्यार्थियों की कमी

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ के दौरान पहली से बारहवीं तक विद्यार्थियों के नामांकन में ८.६६ लाख से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले सत्र में १.४२ करोड़ विद्यार्थियों का नामांकन था, जो इस साल घटकर १.३३ करोड़ रह गया। हालांकि, नामांकन में कमी का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। विभाग के सामने स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की पहचान के साथ रिकॉर्ड में दर्ज विसंगतियों को दूर करने की चुनौती भी है।

राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रोफाइल अपडेट सहित जरूरी कार्यों में लापरवाही को लेकर १२ से अधिक जिलों के जिला परियोजना समन्वयकों (डीपीसी) को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। विभाग ने आधार सत्यापन और विद्यार्थियों के रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

७५ लाख विद्यार्थियों की प्रोफाइल अधूरी

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में ७५.१७ लाख से अधिक विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई है। वहीं, ८,७४,०४५ विद्यार्थी ड्रापबॉक्स में दर्ज हैं, जिनकी स्थिति का सत्यापन किया जाना है। इनमें से करीब ३४,७२९ विद्यार्थियों को अब तक संबंधित स्कूलों में दर्ज नहीं किया गया है। आधार सत्यापन का काम भी अधूरा है। अब तक ८०.६२ प्रतिशत विद्यार्थियों का ही आधार सत्यापन हो पाया है, जबकि १,७०,८०२ विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट नहीं हुई है। ऐसे में नामांकन में आई गिरावट के पीछे वास्तविक रूप से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों और अधूरे डिजिटल रिकॉर्ड की अलग-अलग भूमिका का पता लगाना जरूरी हो गया है।

भोपाल में २० हजार से अधिक नामांकन कम

राजधानी भोपाल में पिछले सत्र की तुलना में २०,३४७ विद्यार्थियों का नामांकन कम दर्ज किया गया है। जिले के १,४९८ स्कूलों में ३,४८,८१२ विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई है। इसके अलावा २,०३७ स्कूलों में शिक्षकों की प्रोफाइल भी अपडेट नहीं की गई है।

राजधानी के जेपी अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेपटरी

एक महीने से एक्स-रे मशीन बंद, मरीज हो रहे परेशान

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार जय प्रकाश अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। अस्पताल की बदहाल व्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पिछले एक महीने से एक्स-रे मशीन बंद पड़ी है, जिसके कारण गंभीर और दूर-दराज से आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जेपी अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में लगी मुख्य एक्स-रे मशीन पिछले एक महीने से तकनीकी खराबी के चलते पूरी तरह बंद पड़ी है। स्थिति यह है कि अस्पताल में रोजाना इलाज कराने पहुँचने वाले सैकड़ों मरीजों को बिना एक्स-रे कराए ही बैरंग लौटना पड़ रहा है या फिर मजबूरी में निजी डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर महंगे दामों में जांच करानी पड़ रही है।

मरीजों की बढ़ रही मुसीबतें

निजी लैब का सहारा: हड्डी टूटने, चोट लगने या आंतरिक जांच के लिए अस्पताल पहुँचने वाले गरीब मरीजों को मजबूरी में बाहर की निजी क्लीनिकों से महंगे दामों पर एक्स-रे करवाना पड़ रहा है, जिससे उनकी जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

जिम्मेदारों की उदासीनता

एक महीने का लंबा समय बीत जाने के बाद भी मशीन का दुरुस्त न होना अस्पताल प्रबंधन और संबंधित तकनीकी अमले की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। आपातकालीन स्थिति में आने वाले मरीजों को भी इस असुविधा के कारण खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल आने वाले म